भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 781
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में जनहित याचिका

781. श्री हनुमान बेनीवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय में दस वर्ष से अधिक समय से लंबित कुल मामले कितने हैं तथा ऐसे लंबित मामलों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका मामलों में दिए गए निर्णय तथा संबंधित सरकारों द्वारा निर्णयों के संबंध में न्यायालय की अवमानना की संख्या तथा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार जनहित याचिकाओं में न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की समय पर अनुपालना सुनिश्चित करने तथा उनकी अवमानना रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है और यदि हां, तो इसके लिए क्या समय-सीमा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31.12.2024 तक दस वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 1,19,906 है । ऐसे लंबित मामलों का विवरण (श्रेणीवार) **उपाबंध** में है । भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 04.02.2025 तक भारत के उच्चतम न्यायालय में दस वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की कुल संख्या 7178 है, जिनमें से 5990 सिविल मामले और 1188 आपराधिक मामले हैं।

भारत के उच्चतम न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान जिन जनहित याचिका मामलों में उपरोक्त उल्लिखित न्यायालयों और संबंधित सरकारों द्वारा निर्णय दिए गए, जिनमें न्यायालय की अवमानना की गई, उनका विवरण नहीं रखा गया है।

*****

उपाबंध

'न्यायालय में जनहित याचिका' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 781 जिसका उत्तर तारीख 07.02.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

31.12.2024 / 01.01.2025 तक दस वर्षों से अधिक के लिए श्रेणीवार लंबित मामले

क्र.सं.	मामलों के प्रकार	कुल
	मुख्य मामले-सिविल पक्ष	
1	पहली सिविल अपील	12343
2	दूसरी सिविल अपील	3778
3	पूर्व पहली अपील	58
4	पूर्व दूसरी अपील	8
5	सिविल विविध अपील	19027
6	सिविल पुनरीक्षण	22
7	सिविल पुनर्विलोकन	199
8	सीमाशुल्क अपील	0
9	आयकर संदर्भ	3
10	अन्य कर संदर्भ	3
11	कर मामले	0
12	उत्पाद-शुल्क अधिनियम संदर्भ	0
13	आयकर अपील	134
14	धन कर अपील	0
15	विक्रय कर पुनरीक्षण	567
16	वसीयती मामले	0
17	कंपनी याचिका	10
18	कंपनी अपील	6
19	कंपनी आवेदन	26
20	कंपनी पूर्व याचिका	0
21	कंपनी वाद	2
22	सिविलअंतरण आवेदन	0
23	कंपनी समापन	39
24	निर्वाचन याचिका	0
25	विशेष अपील (सिविल)	6
26	विशेष अपील (रिट)	319
27	सिविल अवमानना याचिका	174
28	सिविल रिट	39269
29	अन्य मूल वाद	0
30	केंद्रीय उत्पादशुल्क अपील	25
31	प्रत्यारोपण याचिका	0
32	प्रत्याक्षेप	939
33	सिविल संदर्भ	0
34	सिविल विविध आवेदन (वक्फ अधिकरण)	7
	कुल (क)	**76964**
	मुख्य मामले-आपराधिक पक्ष	
1	हत्या संदर्भ	0
2	आपराधिक अपील	27954
3	आपराधिक पुनरीक्षण	7071
4	द.प्र.सं. की धारा 482 के अधीन आपराधिक सिविल याचिका	841
5	द.प्र.सं. की धारा 438 और धारा 439 के अधीन आपराधिक विविध जमानत	0
6	आपराधिक अवमानना याचिका	12
7	आपराधिक संदर्भ	0
8	बंदी प्रत्यक्षीकरण	0
9	आपराधिक अपील की अनुमति	46
10	आपराधिक रिट	13
11	आपराधिक मूल	0
12	आपराधिक पुनर्विलोकन	0
	कुल (बी)	**35937**
	कुल (ए+बी)	**112901**

31.12.2024 / 01.01.2025 तक दस वर्षों से अधिक के लिए श्रेणीवार लंबित मामले

मामलों के प्रकार	कुल
<u>विविध मामले- आपराधिक पक्ष</u>	
आपराधिक विविध आवेदन -	
आपराधिक अपील में जमानत आवेदन	750
जमानत आवेदन और आपराधिक पुनरीक्षण में रोक	35
जमानत आवेदन और आपराधिक विविध याचिका में रोक	490
अपराध में जमानत आवेदन और रोक अपराध अंतरण याचिका + सी आर एल डब्ल्यू	6
अपराध में जमानत आवेदन और रोक अपराध अवमान याचिका	0
जमानत आवेदन और आपराधिक में रोक और अपील की अनुमति	1
आपराधिक विविध आवेदन	20
कुल (सी)	**1302**
आपराधिक स्थानांतरण याचिका	0
बंदी प्रत्यक्षीकरण में रोक	0
कुल (डी)	**0**
कुल (सी+डी)	**1302**
कुल ए+बी+सी+डी	**114203**
विविध मामले-सिविल पक्ष	
<u>सिविल अंतर्वर्ती मामले</u>	
आयकर अपील में रोक	0
विक्रय कर पुनरीक्षण में रोक	5
पहली सिविल अपील में रोक	286
दूसरी सिविल अपील में रोक	13
विविध सिविल अपील में रोक	1770
सिविल पुनरीक्षण में रोक	13
विशेष अपील (सिविल) में रोक	0
सिविल अंतरण आवेदन में रोक	0
विशेष अपील (रिट) में रोक	85
रिट याचिका में रोक	1371
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अपील में रोक	0
सिविल पुनर्विलोकन में रोक	0
सिविल विविध आवेदन में रोक	0
डब्ल्यू. टी. अपील/सीयूएसटीए में रोक	0
ओ.टी. संदर्भ में रोक	1
सीमाशुल्क पहली अपील में रोक	23
सीमाशुल्क दूसरी अपील में रोक	5
सिविल अवमान में रोक	0
कंपनी मामलों में रोक	0
कुल (ई)	**3572**
सिविल विविध आवेदन	1513
सिविल विविध मामलों	611
पूर्व विविध आवेदन	0
उच्चतम न्यायालय में अपील की अनुमति	7
सिविल अंतरण आवेदन	0
कुल (एफ)	**2131**
कुल (ई+एफ)	**5703**
कुल-विविध (सी+डी+ई+एफ)	**7005**
कुल (ए+बी+सी+डी +ई+एफ)	**119906**
जनवरी 2020 से दिसंबर 2024 तक रजिस्ट्रीकृत की गई डीबी अवमानना याचिकाओं की संख्या जो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनवरी-2020 से दिसंबर-2024 तक जनहित याचिका मामले में दिए गए निर्णयों के संबंध में फाइल की गई है ।	297

टिप्पण:- राजस्थान उच्च न्यायालय में मामलों (पीआईएल निर्णयों) के संबंध में कोई डाटा नहीं रखा जाता है, जिनमें संबंधित सरकार द्वारा अवमानना की गई हो ।

****